आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा : भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र सेनानियों ने जेलों में यातनाएँ सहकर संविधान की रक्षा की

जयपुर, 25 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को देश में थोपा गया आपातकाल हमारे लोकतांत्रिक इतिहास पर काला धब्बा है। इस दौरान तत्कालीन सरकार ने मीसा और डीआईआर जैसे अलोकतांत्रिक कानूनों को लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और मौलिक अधिकारों का दमन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सेनानियों ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेलों में कड़ी यातनाएं झेलीं और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वो एक अप्रतिम उदाहरण है।

शर्मा बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित "भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय- संविधान हत्या दिवस-2025" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार ने लगभग एक लाख 40 हजार लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से कई महीनों तक कैद में रखा। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी को भी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन लोकतंत्र के सजग प्रहरी ये सेनानी जीवन की परवाह किए बिना अपने संकल्प पर डटे रहे और आपातकाल का जमकर विरोध किया।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को फिर से बहाल किया है। अब प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और 4 हजार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र सेनानियों का सान्निध्य पाकर उन्हें अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री ने भावी पीढ़ी से सेनानियों से उनके संघर्ष के संस्मरण सुनने और प्रेरणा लेने का आव्हान किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की, मौलिक अधिकारों का हनन किया, मीसा जैसा कानून लाया गया, जिसमें अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी का प्रावधान रखा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के संस्मरणों से संकलित 'लोकतंत्र रक्षा की कहानी-सेनानियों की जुबानी' पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने परिसर में आपातकाल के 50 वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक गोपाल शर्मा सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपातकाल लगने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित "भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय- संविधान हत्या दिवस-2025" कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक गोपाल शर्मा सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।

- **मुख्यमंत्री शर्मा ने बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपातकाल लगने के 50 साल पूरे होने पर आयोजित सम्मेलन "भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय-संविधान हत्या दिवस-2025" कार्यक्रम को संबोधित किया।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा, हमने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को पुनः बहाल किया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रूपए मासिक पेंशन और 4 हजार रूपए की चिकित्सा सहायता दी जा रही है।**

शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी

फ्लोरिडा, 25 जून। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला तीन अन्य चालक दल के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 12 बजकर एक मिनट पर मिशन को लांच किया गया। नासा ने बताया कि गुरुवार शाम चार बजकर 30 मिनट पर डॉकिंग की टाइमिंग है। इस मिशन का संचालन भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। क्रू कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट पर एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर रहा है। इस मिशन का नेतृत्व अमेरिका की कमांडर पैगी व्हिटसन कर रही हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की मिशन विशेषज्ञ हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी। कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च होने के बाद चालक दल एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर परिक्रमा प्रयोगशाला की यात्रा करेगा। नासा ने एक बयान में कहा कि मिशन का डॉकिंग समय गुरुवार, 26 जून को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 4.30 बजे है।

- **शुभांशु भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर एक मिनट पर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे।**

जयपुर-अजमेर हाईवे पर मैथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर जिंदा जला

मोखमपुरा के पास एनएच48 पर हुए हादसे में टैंकर पलटते ही आग लग गई

- **हाईवे पर चल रहे कई वाहन चालक अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भाग गए।**
- **इस हादसे ने दिसंबर 2024 में हुई भांकरोटा दुखांतिका की भयावह यादें ताजा कर दीं, जब एलपीजी टैंकर में आग लगने से हुए हादसे 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे व 35 से ज्यादा लोग झुलस गए थे।**

जयपुर, 25 जून। जयपुर-अजमेर हाईवे पर बुधवार को जयपुर ग्रामीण जिले के मोखमपुरा के पास केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही टैंकर में भीषण आग लग गई। हादसे में वाहन चालक राजेन्द्र यादव टैंकर की केबिन में फंसने से जिंदा जल गया। इस हादसे ने गत वर्ष दिसम्बर में भांकरोटा के समीप इसी हाईवे पर हुए भयावह हादसे की यादें ताजा कर दीं।

थानाधिकारी संजय मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह एनएच 48 पर मोखमपुरा में मेथेनॉल से भरा टैंकर पलटते ही उसमें आग लग जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची और उच्च अधिकारियों और दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल आने से पहले ही वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। टैंकर में लगी आग और धुंआ करीब 300 मीटर दूर से ही नज़र आ रहा था। इस कारण हाईवे पर चल रहीं दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर भी डर गए।

दूदू, बगरू सहित जयपुर से एक दर्जन से ज्यादा दमकल वहाँ पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वाहनों को घटनास्थल के पास नहीं जाने दिया। काफी समय बाद पुलिस ने महला, जोबनेर, दूदू, मोखमपुरा स्टेट हाईवे से वाहनों को डाइवर्ट करके निकालने का प्रयास किया। हादसे की सूचना मिलते ही, एसडीएम बलवीर सिंह, तहसीलदार राघवेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल सहित, अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

टैंकर में भरा मेथेनॉल हाईवे पर बिखर गया। आग फैलने के डर से टैंकर के करीब चल रहीं गाड़ियां हाईवे पर ही रुक गईं। हादसे के करीब आधा घंटे बाद तक हाईवे पर जाम लगा रहा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह जैसे ही हादसा हुआ, लोग अपने वाहनों को छोड़ कर खेतों की तरफ भागे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह जयपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ट्रक पलटा और आग का गोला बन गया। सभी लोग डर गए और कार से उतरकर पीछे की तरफ भागे। अन्य गाड़ी वालों ने भी कार रोकी और खुले स्थान की तरफ भागने लगे। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, हाईवे पर टैंकर पलटने के बाद आग लगते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दमकल वाहन और उच्च अधिकारियों को हादसे की सूचना दी। लेकिन 45 मिनट बाद पहली दमकल पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वाहन चालक की जलकर मौत हो चुकी थी। सूत्रों ने कहा, समय रहते अगर दमकल पहुंचती तो शायद वाहन चालक की जान बच सकती थी। मुख्यमंत्री कार्यालय पर हादसे की सूचना के बाद जयपुर से एक दर्जन दमकल पहुंचीं, तब आग पर काबू पाया गया।

गौरतलब है कि दिसंबर-2024 में इसी हाइवे पर हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं, 35 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए थे। बुधवार को जहां टैंकर पलटा, उस जगह की दूरी भांकरोटा से करीब 30 किलोमीटर है। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले साल हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है। कैमिकल या गैस से भरे टैंकर की सुरक्षा को लेकर कोई सख्ती नहीं हुई है।

अधिकांश अमेरिकावासी ईरान पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आधे ही उत्साहपूर्वक समर्थन करते हैं- जबकि 88 प्रतिशत डेमोक्रेट और 60 प्रतिशत स्वतंत्र मतदाता इसका विरोध करते हैं। यह विभाजन ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो नेतृत्व को लेकर असमंजस और संदेह से जूझ रहा है।

आम लोगों में गहरी चिंता है, 58 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि ये हमले अमेरिका के लिए और ईरान के खतरे को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा देंगे। यहां तक कि जो लोग हमलों का समर्थन करते हैं, उनमें से भी केवल 55 प्रतिशत ही मानते हैं कि इससे खतरा वास्तव में कम होगा। यानी बल प्रयोग का तर्क हमले समर्थकों को भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर पा रहा।

और भी अधिक चिंता की बात यह है कि केवल 32 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिका ने हमले से पहले पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास किए। अधिकांश अमेरिकी जनता यह सवाल कर रही है कि क्या बल प्रयोग वाकई में जरूरी था - और क्या शांति के किसी विकल्प पर गंभीरता से विचार किया गया था?

इस पूरे मुद्दे के मूल में ट्रंप के सैन्य निर्णयों पर बढ़ता अविश्वास है, 55 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें ट्रंप पर "बहुत कम" या "बिल्कुल भी" भरोसा नहीं है कि वे बल प्रयोग को लेकर सही निर्णय लेंगे। केवल 45 प्रतिशत उन्हें "मध्यम" या "बहुत अधिक" भरोसेमंद मानते हैं। डेमोक्रेट में यह अविश्वास अत्यधिक (88 प्रतिशत) है, और स्वतंत्र मतदाताओं में भी यह काफी गहरा (62 प्रतिशत) है।

अमेरिकी जनता अब राष्ट्रपति के युद्ध-संबंधी अधिकारों पर नियंत्रण की मांग कर रही है। सर्वे में शामिल 65 प्रतिशत मानते हैं कि ट्रंप को आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस से अनुमति लेनी चाहिए। यहां तक कि उनकी खुद की पार्टी में भी 39 प्रतिशत रिपब्लिकन इस बात से सहमत हैं।

उम्र इस राजनीतिक विभाजन में एक और परत जोड़ती है। अमेरिका में 35 वर्ष से कम उम्र के अमेरिकी इन हमलों को लेकर सबसे अधिक संशय में हैं जहां 68 प्रतिशत विरोध में हैं वहीं 45 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें ट्रंप के सैन्य निर्णयों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। युवा रिपब्लिकन समर्थकों में केवल 20 प्रतिशत ही इन हमलों का जोरदार समर्थन करते हैं, जबकि पुराने रिपब्लिकन में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर यह पीढ़ीगत अंतर आने वाले महीनों में असर डाल सकता है।

एक बात पर लगभग सर्वसम्मति है, वह यह है: अमेरिकी सैनिकों को जमीनी युद्ध में नहीं भेजना चाहिए। केवल 9 प्रतिशत लोग ईरान में जमीनी सैनिक भेजने का समर्थन करते हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और ट्रंप द्वारा युद्धविराम की घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यपूर्वी संकट से चिंतित हैं, वे एकतरफा सैन्य कार्रवाई पर भरोसा नहीं करते, और उस व्यक्ति को लेकर और अधिख सशंकित हैं जो फैसले ले रहा है। ट्रंप ने भले ही हमला करने का आदेश दिया हो, लेकिन जनता का विश्वास जीतने की लड़ाई अभी बाकी है।

दिल्ली के नौसेना भवन का यूडीसी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार

- **राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने आरोपी विशाल यादव को गिरफ्तार किया**
- **इस गिरफ्तारी से देश की खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।**
- **सूत्रों ने बताया कि हरियाणा निवासी विशाल यादव पाकिस्तान की महिला हैंडलर के संपर्क में था, जो प्रिया शर्मा के नकली नाम से विशाल से बात कर रही थी।**

जयपुर, 25 जून। देश की राजधानी स्थित नौसेना भवन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान पुलिस की खुफिया विंग ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी ने देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए, विशाल यादव, निवासी पुनसिका रेवाड़ी, हरियाणा, को बुधवार 25 जून को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत दबोचा है।

महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी सुरक्षा, विष्णुकांत गुप्ता ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान लगातार निगरानी रख रही थी। इसी निगरानी के दौरान यह जानकारी सामने आई कि नौसेना भवन दिल्ली में डायरैक्टोरेट ऑफ डॉकयार्ड में कार्यरत विशाल यादव सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर के निरंतर संपर्क में था। यह महिला, जिसका छद्म नाम प्रिया शर्मा बताया जा रहा है, विशाल को पैसों का लालच देकर नौसेना भवन से सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं निकालने के लिए उकसा रही थी।

प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। वह महिला पाक हैंडलर को संवेदनशील सूचनाओं के एवज में अपने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग अकाउंट में यूएसडीटी और सीधे अपने बैंक खातों में धनराशि प्राप्त कर रहा था।

संदिग्ध के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक विश्लेषण करने पर जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, वे और भी गंभीर हैं। उसके मोबाइल से मिली चैट और दस्तावेजों के अवलोकन से पता चला है कि विशाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान के दौरान भी नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाएं महिला पाक हैंडलर को उपलब्ध कराई थीं। जो दर्शाता है कि वह लंबे समय से इस जासूसी रैकेट का हिस्सा था।

धर्मशाला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओर डायवर्ट हो गया, जिससे शेडों में आराम कर रहे मजदूर बह गए। बहे हुए ज्यादातर मजदूर श्रीनगर के बताए जा रहे हैं। एक शव टिल्लू के पास और दूसरा नगूनी में मिला। नगूनी में गई एसडीआरएफ टीम से अभी संपर्क नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने जल विद्युत परियोजना पर पेड़ कटाई और मलबा डालने का आरोप लगाया, जिससे नाले का बहाव बदला।

'हमारे परमाणु ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ'

तेहरान, 25 जून। ईरान ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि अमेरिकी हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को बुरा नुकसान हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई की तरफ से बुधवार को इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया कि यह नुकसान कैसा है और किस हद का हुआ है। अमेरिका ने रविवार 22 जून को बी-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बमों की मदद से ईरान के परमाणु अड्डों को निशाना बनाया था।

साल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नए नियम के अनुसार, कक्षा 10 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा के पहले चरण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जबकि दूसरे फेज में शामिल होने का ऑप्शन होगा। आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा।

'28 दिन अवैध हिरासत में रखा, अब 5 लाख रु. का मुआवज़ा दे यूपी सरकार'

- **सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन का दोषी करार दिया**

नयी दिल्ली, 25 जून। उच्चतम न्यायालय ने जमानत आदेश के बावजूद 28 दिनों तक एक व्यक्ति को जेल में रखने को स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उस व्यक्ति को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ बुधवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि गाजियाबाद जेल प्रशासन, 29 अप्रैल को पारित शीर्ष अदालत के आदेश और 27 मई के औपचारिक रिहाई आदेश के बावजूद आरोपी को रिहा करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

पीठ ने कहा, भगवान जानता है कि ऐसे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं।न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तकनीकी बातों पर जोर देने वाले जेल अधिकारियों के आचरण की निंदा की। उन्होंने गाजियाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसकी जांच करने और व्यक्ति की रिहाई में 28 दिनों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दिया।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा तीन और पांच (आई) के तहत गिरफ्तार किया गया वह व्यक्ति 24 जून तक हिरासत में रहा। अधिकारियों ने सफाई दी कि जमानत आदेश में एक उप-धारा की चूक के कारण व्यक्ति की रिहाई नही हो पायी थी।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,स्वतंत्रता एक व्यक्ति को दी गई एक बहुत ही मूल्यवान और अनमोल अधिकार है। इसे इन बेकार की तकनीकी बातों पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब इस अदालत ने एक वैध आदेश पारित करके स्वतंत्रता दी है, तो उसे कैसे छीना जा सकता है?

जेल अधिकारियों और राज्य प्रशासन पर तीखी टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा,क्या किसी उपधारा को छोड़ देना किसी को हिरासत में रखने का वैध आधार है। अगर हम स्पष्ट न्यायिक आदेशों के बावजूद लोगों को सलाखों के पीछे रखते हैं तो हम आज जन को क्या संदेश दे रहे हैं।

12 दिन का युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से इन्कार किया, लेकिन कहा कि अगर इज़रायल 4 बजे सुबह (तेहरान समय) तक हमले रोक दे, तो वह भी आगे नहीं बढ़ेगा। इज़रायल ने 24 जून की सुबह तेहरान के पास एक रडार स्ट्राइक की, लेकिन ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद हमले पर रोक लगा दी। इसका क्षेत्रीय और वैश्विक असर देखा गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई (वैस्ट टैक्सस इन्टरमीडिएट/ डब्ल्यु.टी.आई. 3.2 प्रतिशत नीचे, ब्रैंट 3.4 प्रतिशत नीचे) और अमेरिकी शेयर बाज़ार के वायदा सूचकांक (स्टॉक फ्यूचर्स) में बढ़त दर्ज की गई, जो कि क्षेत्रीय तनाव में कमी के प्रति राहत का संकेत था। इज़रायली हवाई अड्डों ने सामान्य नागरिक उड़ानें फिर से शुरु कर दीं; सैन्य प्रतिबंधों में ढील दी गई। भारत ने इस युद्धविराम का स्वागत किया और राजनयिक समर्थन की पेशकश की। युद्धविराम अत्यधिक नाजुक है: 24 जून को आरंभिक उल्लंघनों और मिसाइल हमलों से स्पष्ट है कि यह अभी भी अस्थिर ही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने उसके कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है, पूरी तरह नष्ट नहीं किया।

ईरान की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग रोकने की घोषणा की, जिससे पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ गई है। आगे की संभावनाएँ देखी जाएं तो यह युद्धविराम अमेरिका, विशेषकर ट्रंप द्वारा जारी राजनयिक दबाव पर निर्भर है, साथ ही, दोनों पक्षों द्वारा आगे और हमले नहीं करने के निर्णय पर। स्थिति बेहद विस्फोटक व संवेदनशील है; किसी भी मिसाइल हमले या हवाई हमले से यह युद्धविराम टूट सकता है।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी को तरजीह देते हुये, उनकी अतिशयोक्ति से भरी प्रशंसा करने के लिए। सूत्रों के अनुसार, "अमित शाह ने भी नरेन्द्र मोदी को सलाह दी है कि वे शशि थरूर को भाजपा में शामिल न करें, क्योंकि वे "एक और सुब्रमण्यम स्वामी" साबित हो सकते हैं, यानी, वे राजनीतिक रूप से अनिश्चित और अप्रत्याशित हैं। शाह का मानना है कि थरूर राजनीतिज्ञ नहीं हैं।"शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा है कि वे भाजपा की गोद में बैठने नहीं जा रहे। माना जा रहा है कि वे भाजपा में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन इस बात से आहत हैं कि उनकी खुद की पार्टी के कुछ लोग उन्हें बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर प्रकरण की आख़िरी पंक्ति अभी नहीं लिखी गई है!!

नाबालिग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन कॉलेज के बाहर उसे पूर्व परिचित अभियुक्त मिला था। वह उसे घर छोड़ने के नाम पर अपने साथ ले गया।

रास्ते में अभियुक्त ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे जयपुर में होश आया। तब अभियुक्त उसे बस से पटना ले गया और बाद में भोपाल ले आया। जहां उसने करीब एक सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि यहां से अभियुक्त उसे वापस जयपुर ले आया और मुहाना मंडी के पास किराए के कमरे में रखा और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

वहीं 20 अक्टूबर पुलिस आकर उसे लग गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी बहन की सगाई पीड़िता के भाई के साथ हुई थी और वह उसके घर आता-जाता था। इस दौरान उनके बीच प्रेम हो गया और पीड़िता ने अपने आप को वयस्क बताया था।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"आपने राजनीतिक, आर्थिक और मीडिया संस्थापन का मुकाबला किया और आपने उन्हें हरा दिया। अब सामान्य चुनाव में जीत की ओर बढ़ें"

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ममदानी को क्वींस में आयोजित विजय के एक समारोह में यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "मित्रो, हम कामयाब हो गये हैं। मैं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए आपका डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनूँगा। हमने हारलेम से बे रिज तक जीत हासिल की है।" जब कुओमो ने चुनाव में हार स्वीकार की, तो उन्होंने कहा: "आज की रात हमारी नहीं थी। आज की रात उनकी थी। वे इसके हकदार थे। उन्होंने जीत हासिल की।" ममदानी की वेबसाइट में कहा गया है कि उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर कामकाजी वर्ग के लिए संघर्ष किया, जिसमें टैक्सी चालकों के साथ भूख हड़ताल कर 450 मिलियन डॉलर से अधिक की ट्रांसफॉर्मेटिव ऋण राहत प्राप्त की, राज्य बजट में 100 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम जुटाई और सबवे सर्विस को बढ़ाया, और एक सफल शुल्क-मुक्त बस पायलट प्रक्षेपण किया। इसके अलावा, न्यूयॉर्कवासियों को संगठित करके प्रस्तावित डर्टी पावर प्लांट की योजना रद्द करायी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, "जीवन यापन की लागत (खर्च) कामकाजी लोगों के लिए बहुत अधिक है, लेकिन ज़ोहरान का मानना है कि सरकार इस लागत को कम कर सकती है और हमारे शहर में जीवन को आसान बना सकती है, वे किराया कम करने, विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने और परिवार पालने को आसान बनाने के लिए हर उपलब्ध साधन का उपयोग करेंगे।"

ममदानी ने वादा किया है कि वे मेयर बनने के बाद तुरंत सभी स्थिर किराएदारों के लिए किराया स्थिर कर देंगे और न्यूयॉर्क वासियों को घर बनाने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे और किराया कम करेंगे।

फास्ट और मुफ्त बसों का वादा करते हुए, उन्होंने प्रचार में कहा कि वे मेयर बनने के बाद हर शहर की बस का किराया स्थायी रूप से समाप्त कर देंगे और उन्हें तेज़ गति देने के लिए प्राथमिकता लेन, बस क्यू जंप सिग्नल और डेडिकेटेड लोडिंग ज़ोन का निर्माण करेंगे, ताकि डबल पार्किंग करने वाले लोगों से बचा जा सके।

ममदानी न्यूयॉर्क के 6 सप्ताह से लेकर 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त देखभाल व्यवस्था लागू करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी परिवारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रोग्रामिंग हो।

खाद्य कीमतों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण, उनके प्रचार में वादा किया गया कि वे मेयर बनने के बाद शहर के स्वामित्व वाले किराना स्टोरों का एक नेटवर्क बनाएंगे, जो कीमतों को कम रखने पर केन्द्रित होंगे, न कि मुनाफा कमाने पर।

उन्होंने अपने प्रचार में कहा, ममदानी के पास जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए शहर के स्वामित्व वाले किराना स्टोर, सार्वभौमिक बाल-देखभाल केन्द्र और अन्य साहसिक प्रस्तावों की योजना है, और उन्हें यह भी पता है कि इसके लिए पैसा कहां से आयेगा। उनकी "राजस्व योजना" के तहत, कॉर्पोरेट टैक्स दर को न्यू जर्सी के 11.5 प्रतिशत से मैच करने तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 5 बिलियन डॉलर की आय होगी। और वे न्यूयॉर्क के सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगों, जो सालाना 1 मिलियन डॉलर से अधिक कमाते हैं, पर फ्लैट 2 प्रतिशत टैक्स लगाएंगे (इस समय शहर की आयकर दर लगभग समान है, चाहे आप 50,000 डॉलर कमाते हों या 50 मिलियन डॉलर)।" उन्होंने यह भी कहा कि वे सामान्य खरीदारी-सुधार लागू करेंगे, बिना निविदा वाले अनुबंधों को समाप्त करेंगे, अधिक टैक्स ऑडिटर्स नियुक्त करेंगे, और भ्रष्ट मकान मालिकों से जुर्माना वसूलने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे अतिरिक्त 1 बिलियन डॉलर की राशि जुटायी जाएगी। उनके प्लेटफॉर्म के अनुसार, "न्यूयॉर्क बहुत महंगा है। ज़ोहरन लागत को कम करेंगे और जीवन को आसान बनाएंगे।" न्यू यॉर्क सिटी मेयर चुनाव 4 नवंबर, 2025 को होना है।

ममदानी के बारे में दिलचस्प विवरण सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही अपनी मां मीरा नायर को हैरी पॉटर फिल्म निर्देशित करने का एक प्रस्ताव ठुकराने और इसके बजाय "द नेमसेक" फिल्म निर्देशित करने के लिए राजी किया था। 2018 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वीर सांघवी को दिये एक इन्टरव्यू में, नायर ने इस बारे में खुलासा किया था कि उन्हें हैरी पॉटर के पांचवे भाग "ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स" को निर्देशित करने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन ममदानी ने उन्हें अपना मन बदलने के लिए राजी कर लिया। 67-वर्षीय फिल्म निर्माता मीरा नायर ने कहा था, "मैंने यह प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं "वैनिटीफेयर" को निर्देशित करने में व्यस्त थी। मेरी सास, जो मेरे लिये माँ जैसी थीं, का न्यूयॉर्क में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण देहान्त हो गया था।" उन्होंने कहा, "मैं गहरे दुख में थी। लेकिन उस समय मैंने झुम्पा लाहिरी का खूबसूरत उपन्यास "द नेमसेक" पढ़ा। यह भी एक माता-पिता के निधन के बारे में था। फिर मैंने तय किया कि इस पर एक फिल्म बनाऊं। इसके बाद मुझे हैरी पॉटर निर्देशित करने का प्रस्ताव मिला।"

उन्होंने आगे बताया, "मैंने अपने 14 साल के बेटे से इसके बारे में पूछा। उसने मुझसे कहा कि हैरी पॉटर बनाने के लिए बहुत से अच्छे निर्देशक हैं, लेकिन ऐसा केवल एक निर्देशक है, जो "द नेमसेक" बना सकता है।"

मीरा फिर "द नेमसेक" निर्देशित करने लगीं, जो समीक्षकों की नज़र में, अब तक की उन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक रही, जो किसी पुस्तक के आधार पर बनी हैं। यह फिल्म झुम्पा लाहिरी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसमें बांग्लादेशी आप्रवासी अशोक (इरफान खान) और आशिमा (तब्बू) के बेटे गोगोल गांगुली की यात्रा की कहानी है, जो अमेरिका में अपनी पहचान को दो अलग-अलग संस्कृतियों के बीच ढूंढने की कोशिश करता है। ममदानी ने न केवल अपनी मां को "द नेमसेक" निर्देशित करने के लिए मनाया, बल्कि उन्होंने काल पेन्न को गोगोल के रूप में कास्ट करने के लिए भी प्रेरित किया, क्योंकि वे इस अभिनेता की 2004 की फिल्म "हैरॉल्ड एंड कुमार गो टु वाइट कैसल" के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे रोज़ाना मीरा से पेन्न को यह भूमिका देने के लिए कहते रहते थे।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908